अमला आधा, कैसे दूर हो ट्रैफिक की बाधा

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 14 मार्च। प्रदेश के सभी बड़े शहरों में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन शहरों में ट्रैफिक को सम्हालने के लिए पुलिस के पास अमले की बेहद कमी है। हालत यह है कि प्रदेश में जितने पद भरे हैं उससे ज्यादा पद खाली हैं।

राजधानी रायपुर सहित सभी बड़े शहरों में ट्रैफिक का बुरा हाल है। लेकिन ट्रैफिक के अमले को नियंत्रित करने के लिए विभाग के पास स्टाफ भी कम है। राजधानी रायपुर एवं जिले में सिपाहियों से लेकर अफसरों तक के तीन सौ 64 पद स्वीकृत हैं। लेकिन इसके आधे पद भी भरे नहीं हैं। वर्तमान में 179 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 185 पद खाली पड़े हुए हैं। राजधानी बनने के बाद शहर का तेजी से विस्तार हुआ है और लगभग हर साल वाहनों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। राजधानी में हर सड़क पर ट्रैफिक का बुरा हाल रहता है। सड़कों पर जाम लगा रहता है। लेकिन इसे सम्हालने और नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक के सिपाही तक मौजूद नहीं रहते। विभाग का कहना है कि जब स्वीकृत पद से आधे लोग काम कर रहे हों तो इतने बड़े शहर के ट्रैफिक को कैसे ठीक किया जा सकता है।

रायपुर की तरह दूसरे जिलों का भी यही हाल है। ट्वीन सिटी वाले दुर्ग जिले में तो और भी बुरा हाल है। वहां तो सिर्फ एक तिहाई पद ही भरे हुए हैं। दुर्ग जिले में दुर्ग और भिलाई दो बड़े शहर हैं। लेकिन वहां अमला बहुत कम है। दुर्ग जिले के लिए ट्रैफिक में कुल 301 पद स्वीकृत हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ 110 कर्मचारी-अधिकारी काम कर रहे हैं। यानी 191 पद खाली पड़े हुए हैं। एक तिहाई कर्मचारियों में दो बड़े शहरों के अलावा कई छोटे शहरों के ट्रैफिक को दुरूस्त करने ट्रैफिक पुलिस के लिए वाकई मुश्किल का काम है।

प्रदेश के तीसरे बड़े शहर वाले बिलासपुर जिले में कुल 155 पद स्वीकृत हैं। इनमें सिपाही से लेकर डीएसपी तक के सिर्फ 59 पद भरे हुए हैं और इससे दुगुने यानी 96 पद खाली पड़े हुए हैं। बिलासपुर शहर भी प्रदेश की न्यायधानी है और पिछले कुछ वर्षों में इस शहर का काफी तेजी से विकास हुआ है। रायपुर की तरह वहां भी वाहनों की संख्या तेजी से बड़ी है। लेकिन अमले की कमी के कारण वहां भी ट्रैफिक का बुरा हाल है। राजनांदगांव जिले में कुल 35 पद स्वीकृत हैं इनमें भी सिर्फ 14 पद ही भरे हुए हैं और 21 पद खाली पड़े हुए हैं। यानी दर्जनभर लोगों के जिम्मे पूरे शहर के ट्रैफिक को सम्हालने का है। कुछ साल पहले बने तीन जिलों कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी में तो अब तक ट्रैफिक का कोई पद ही मंजूर नहीं है। यहां पर ट्रैफिक को सम्हालने की जिम्मेदारी जिला पुलिस पर ही है। कवर्धा में तो मुख्यमंत्री के गृह नगर होने के कारण ट्रैफिक दुरूस्त करने में और भी दिक्कत आती है।

कोरबा भी प्रदेश की बड़ी औद्योगिक नगरी है। पिछले कुछ वर्षों में इस शहर का भी काफी तेजी से विकास हुआ है। ट्रैफिक का दबाव भी काफी बढ़ा है। लेकिन यहां भी सिर्फ 34 लोगों का अमला स्वीकृत है। जिनमें 21 पद भरे हुए हैं और 15 पद खाली पड़े हुए हैं। जांजगीर में भी दूसरे नए जिलों की तरह पद मंजूर नहीं है। जबकि रायगढ़ में कुल 58 अधिकारियों-कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। रायगढ़ भी प्रदेश की एक प्रमुख औद्योगिक नगरी है। यहां भी भारी वाहनों के ज्यादा चलने के कारण ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ा है। लेकिन इसके मुकाबले कर्मचारियों-अधिकारियों की संख्या काफी कम है। यहां पर 31 पद भरे हुए हैं जबकि 27 पद खाली पड़े हैं।

सरगुजा ही प्रदेश का एक मात्र जिला है जहां के सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं। यहां कुल 22 लोगों का स्टाफ स्वीकृत है जिनमें सभी भरे हुए हैं। कोरिया, जशपुर और बलरामपुर में भी ट्रैफिक के पद स्वीकृत नहीं हैं। सुरजपुर जिले में 24 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 11 भरे हुए हैं और 15 खाली हैं। जगदलपुर जिले में 21 पद स्वीकृत हैं जिनमें 14 भरे हुए है और 7 खाली पड़े हैं। कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायपुर और बीजापुर जिले में ट्रैफिक का कोई अमला नहीं है। यद्यपि विभाग और पुलिस के लोगों का कहना है कि ट्रैफिक दुरूस्त करने के लिए समय-समय पर होमगार्ड्स के जवानों की भी मदद ली जाती है। इसी तरह जिन जिलों में ट्रैफिक के सिपाही नहीं है वहां पर जिला पुलिस के सिपाहियों को ट्रैफिक दुरूस्त करने के लिए लगाया जाता है लेकिन जिला पुलिस में भी अमले की कमी होने और उनका अन्यत्र ड्यूटी लगने पर ट्रैफिक नियंत्रण में काफी दिक्कतें होती हैं।

कोयला खदान हथियाने उद्योगपतियों में होड़

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 14 मार्च। प्रदेश में बिजलीघर लगाने के बहाने उद्योगपतियों की नजर बेशकीमती खदानों पर लगी है। जानकारों के मुताबिक पिछले दस सालों में बिजलीघर लगाने 71 एमओयू किए गए। इसके लिए उद्योगपतियों को 22 कोल ब्लाक का आबंटन किया जा चुका है। इसमें से दो निजी कंपनियों को छोड़कर बिजलीघर लगाने का काम शुरू नहीं किया है।

प्रदेश में कोयला खदानों को हथियाने होड़ मची हुई है। इसके लिए निजी कंपनियां राज्य सरकार से बिजलीघर लगाने लगातार एमओयू कर रहे हैं। खनिज विभाग के अफसरों के मुताबिक पिछले दस सालों में 28 कोल ब्लाक का पता चला है। इन सभी कोल ब्लाकों को निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें 22 कोल ब्लाक का आबंटन भी कर दिया गया है।

सूत्रों की मानें तो कई कंपनियों ने खनन भी शुरू कर दिया है। जबकि राज्य में बिजली घर लगाने केवल दो जिंदल पावर और लेंको अमरकटंक पावर कंपनी ने काम शुरू किया है। विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन कंपनियों ने खनन का काम कर दिया है। इसमें जिंदल स्टील एंड पावर, मोनेट स्पात, जायसवाल निको लिमिटेड और रायपुर एलायज एंड स्टील लिमिटेड शामिल हैं।

कोल ब्लाक का खनन लायसेंस प्राप्त करने सभी कंपनियों ने बिजलीघर लगाने एमओयू किया है। लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने संयंत्र लगाने की दिशा में कोई काम नहीं किया है। खनिज सचिव आरएस विश्वकर्मा ने कहा कि 28 में से 22 कोल ब्लाकों का आबंटन किया जा चुका है। बिजलीघर लगाने के लिए कंपनियों को अभी तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति नहीं दी गई है जिसकी वजह से संयंत्र लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले लोगों पर शासन की नजर है। बिजलीघर का काम शुरू होने के बाद ही कोल ब्लाक के खनन की अनुमति दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में कोयले का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत है। यहां के कोयले की क्वालिटी भी काफी अच्छी मानी जाती है। राज्य का कोयला दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। पूरे देश में राज्य की कोयले की अच्छी खासी मांग है। यही वजह है कि उद्योगपति बिजली संयंत्र लगाने से पहले कोयले के खदान हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। जानकारों का कहना है कि राज्य के कई बड़े उद्योगपति पावर प्लांट के लिए आबंटित कोयले का उपयोग फर्नेस और दूसरे कामों में भी करते हैं। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि कम क्षमता के बिजलीघर लगाने के नाम पर कोल ब्लाक का बड़ा हिस्सा आबंटित करा लिया जाता है।

कमल विहार योजना की हजार आपत्तियों की सुनवाई पूरी

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 14 मार्च। कमल विहार योजना के लिए की गई ढाई हजार आपत्तियों में से एक हजार आपत्तियों की सुनवाई पूरी हो गई है। इनमें से लगभग 7 सौ आपत्तियां सुनवाई के योग्य ही नहीं पाई गई। सुनवाई के दौरान पता चला कि आपत्तियों में से कई ऐसी आपत्तियां ऐसी हैं जो योजना के लिए निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं। सुनवाई 16 मार्च तक चलेगी। सुनवाई के बाद आरडीए ने पूर्व में घोषित प्रारूप के कुछ बिंदुओं को संशोधित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

प्रारूप में होगा संशोधन

योजना का विरोध करने की मुहिम के दौरान दूसरे इलाकों के नागरिकों ने भी रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति कर दी। आपत्तियों की सुनवाई के दौरान अफसरों को पता चला कि कृष्ण नगर, शिव मंदिर के आसपास व अन्य क्षेत्रों से करीब 7 सौ से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। कमल विहार योजना के लिए तैयार ले-आउट के अंतर्गत ये क्षेत्र नहीं आते हैं। इन आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी गई।

रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ अमित कटारिया ने बताया कि अभी तक लगभग एक हजार आपत्तियों की सुनवाई हो चुकी है। इनमें से लगभग 70 फीसदी आपत्तियां स्कीम के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों से की गई हैं। शेष आपत्तियों की सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुनकर उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। सुनवाई के बाद प्रारूप में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

गौरतलब है कि कमल विहार योजना का विरोध कई गांवों में हो रहा है। योजना का प्रारूप घोषित होने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया था। इस मामले को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना के कारण उनकी जमीन का बड़ा हिस्सा सड़क, नाली, मनोरंजन स्थल सहित अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण करने में किया जाएगा, जिससे उनकी जमीन का लगभग 40 फीसदी हिस्सा ही उन्हें मिलेगा।

इधर आरडीए के अफसरों का कहना है कि कुछ जमीन दलाल इसका विरोध अपने हित साधने के लिए कर रहे हैं। कमल विहार योजना के अंतर्गत करीब 2 हजार एकड़ क्षेत्र में जमीन बिक्री करने वाले जमीन दलालों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास नहीं कराया। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, मनोरंजन स्थल जैसे अन्य स्थानों के लिए पर्याप्त जगह छोड़े बगैर ही अंधाधुंध प्लाटों की बिक्री की जा रही है। भविष्य में इन स्थानों पर बनने वाली कालोनियों में रहने वाले लोगों को नक्शा पास कराने, मकान बनाने और ऋण लेने में दिक्कतें होगी। ऐसी जमीन खरीदने वाले लोगों को राहत देने के लिए ही कमल विहार योजना शुरू की गई है।

सूत्रों ने बताया कि अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों ने ही भ्रम फैलाकर बड़ी तादाद में आपत्तियां दर्ज कराई हैं। मकान तोड़ने व बस्तियां उजाड़ने की अफवाह फैलने के कारण ही अधिकांश लोगों ने आरडीए के समक्ष आपत्ति की।

तौल कर दिया जाएगा गैस सिलेंडर

रायपुर, 14 मार्च। उपभोक्ताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए नाप-तौल विभाग द्वारा सभी गैस विक्रेताओं को पत्र जारी कर निर्धारित मात्रा में गैस सिलेण्डर की आपूर्ति करने और घर पहुंच सेवा की स्थिति में प्रत्येक रिक्शा/ऑटो में उपयुक्त क्षमता का प्रमाणिक स्प्रिंग बैलेंस हॉकर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी उपभोक्ता गैस सिलेण्डर की मात्रा से संबंधी शिकायत राजधानी रायपुर में सुंदर नगर के प्लांट नम्बर-14, आम बगीचा स्थित उप नियंत्रक कार्यालय, नाप तौल विभाग से संपर्क कर दर्ज करा सकते हैं, प्राप्त शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

नाप-तौल विभाग के सहायक नियंत्रक एस.एस.राय ने बताया कि उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन से कम मात्रा में रसोई गैस आपूर्ति संबंधी शिकायतों पर नियंत्रक नाप-तौल दिलीप वासनीकर के निर्देशानुसार नाप-तौल विभाग के निरीक्षक दलों द्वारा आकस्मिक छापामार कार्रवाई करते हुए राजधानी रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थित गैस फीलिंग प्लांट और गैस गोदामों की लगातार तीन दिन सघनता से जांच की गई।

विद्युत कम्पनी के दो संयंत्रों ने बनाया कीर्तिमान

रायपुर, 14 मार्च। राज्य सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनी के कोरबा पश्चिम और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृहों ने सबसे कम तेल की खपत और सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन का एक नया कीर्तिमान बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इन उपलब्धियों के लिए अपने निवास पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम में इन दोनों बिजली संयंत्रों के मुख्य अभियंताओं श्री जी.पी. शर्मा और श्री आर.डी. सोनकर को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर कम्पनी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री पी. जॉय उम्मेन, ऊर्जा सचिव श्री अमन कुमार सिंह और कम्पनी के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को पावर कम्पनी के अधिकारियों ने बताया कि कोरबा पश्चिम ताप बिजली संयंत्र ने पिछले माह फरवरी 2010 में अपने जीवन काल के किसी एक माह में सर्वाधिक प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ) पर विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान बनाया है। इस अवधि में 100.2 प्रतिशत पी.एल.एफ. सहित दशमलव शून्य आठ मिलीलीटर प्रति किलोवाट प्रति घंटे की ईधन खपत कर मासिक उत्कृष्ट कार्य निष्पत्ति का प्रदर्शन इस बिजली संयंत्र ने किया है। उल्लेखनीय है कि तकनीकी दृष्टि से किसी भी विद्युत संयंत्र का जीवनकाल 25 वर्ष माना जाता है और कोरबा पश्चिम ताप विद्युत संयंत्र की उम्र इससे अधिक हो गयी है। इसके बावजूद इस बिजली संयंत्र ने प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ) के नया कीर्तिमान बनाकर चालू वर्ष में 87.96 प्रतिशत वार्षिक पी.एल.एफ. पर चल रहा है और विगत पांच वर्षों से यह लगातार 85 प्रतिशत से अधिक पी.एल.एफ. प्रदर्शित कर रहा है। इसी कड़ी में कोरबा स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप बिजली संयंत्र (कोरबा पूर्व) द्वारा अब तक 87.2 प्रतिशत वार्षिक पी.एल.एफ. दर्ज कर अपने इस कीर्तिमान को कायम रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने किया मुख्य अभियंताओं का सम्मान

अधिकारियों ने यह भी बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप बिजली संयंत्र के विधिवत क्रियाशील होने के बाद ही छत्तीसगढ़ में जीरो पावर कट की स्थिति बनी और इसके फलस्वरूप विगत दो वर्षों से बिजली की कटौती नहीं हो रही है। इस विद्युत संयंत्र ने बिजली के उत्पादन में सबसे कम तेल की खपत की है, जो प्रति किलोवाट प्रति घंटा सिर्फ दशमलव 77 मिलीलीटर है। यह किसी भी ताप बिजली संयंत्र में न्यूनतम तेल खपत का एक नया कीर्तिमान है।

अशासकीय संस्थाओं में भी मिलेगी मासिक शिष्यवृत्ति

रायपुर, 14 मार्च। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2010-11 में छत्तीसगढ़ के सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय प्री मेट्रिक छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी साढ़े चार सौ रूपए की दर से मासिक शिष्यवृत्ति देने का निर्णय लिया है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि विभागीय प्री-मेट्रिक छात्रावासों और आश्रम शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पहले साढ़े तीन सौ रूपए मासिक की दर से शिष्यवृत्ति दी जा रही थी। प्रदेश सरकार ने विगत वर्ष 2008-09 से इसमें एक सौ रूपए की वृद्धि कर दी है। इस प्रकार विभाग के शासकीय प्री-मेट्रिक छात्रावासों और आश्रम विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को साढ़े चार सौ रूपए की दर से हर महीने शिष्यवृत्ति मिल रही है। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार अब आगामी वित्तीय वर्ष 2010-11 से सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में प्रवेशित अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को भी इसी दर पर शिष्यवृत्ति मिलेगी।

मिर्जा मसूद का 'चेखव'

नाटक चर्चा

अंतोन चेखव का विश्व साहित्य, खासकर रुसी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। उनकी कहानियां सर्वकालिक मानी जाती हैं तो इसलिए कि वे मानव मन के अद्भुत चितेरे है। अपनी कहानियों में उन्होंने तत्कालीन रुसी समाज, उसकी विकृतियों को शिद्दत से उभारा है। इन विकृतियों से उभरा तमाशा और इस तमाशे से उभरा हास्य केवल पाठकों का मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि पाठकों के सामान्य अनुभवों को 'असामान्य' के स्तर पर ले जाता है। इसलिए उनकी कहानियां आज भी जीवंत है और भारतीय मन को गुदगुदाती है।

रंगकर्म के क्षेत्र में कोसल नाट्य अकादमी और मिर्जा मसूद नए नाम नहीं है, क्योंकि उनके खाते में 60 से अधिक रंग प्रस्तुतियां दर्ज है। इस खाते में 'चेखव का रचना संसार' भी दर्ज हो चुका है। मुक्ताकाश में कल चेखव की चार कहानियों एक कलाकृति, पियानो बजाने वाला, बदला और प्रस्ताव की रंग प्रस्तुतियां की गई। चारों प्रस्तुतियां दर्शकों द्वारा सराही गई 'प्रस्ताव' तो बेहद।

अब मेरे सामने दो 'चेखव' है। एक चेखव वो है, जिसे 12वें मुक्तिबोध नाट्य समारोह में रंजीत कपूर ने पिछले वर्ष पेश किया था। दूसरे चेखव ये है, जिसे मिर्जा मसूद ने प्रस्तुत किया है। इन दोनों चेखवों को जोड़कर बात करना कुछ बुरा नहीं होगा।

रंजीत कपूर की प्रस्तुति बेहद सफल रही थी। उन्होंने पांच कहानियों को मंचित किया था बिना किसी 'गैप' के। सूत्रधार के रूप में स्वयं चेखव कहानियों को गति दे रहे थे। एक के बाद दूसरी कहानी की रंग प्रस्तुति रंगदर्शकों पर पहले के बने प्रभाव को बिना मिटाए उनकी रंग मानस का विस्तार करती थी। मिर्जा मसूद 'गैप' देना पसंद करते हैं।

किसी 'चेखव' को सूत्रधार के रूप में सामने नहीं रखते। मंच की पृष्ठभूमि की उद्घोषणा तथा नाट्य परिचय से दूसरी कहानी मंचित होती है। इस गैप के जरिए वे दर्शकों की रंग संवेदनाओं पर विराम लगाते हैं और उन्हें दूसरी प्रस्तुति के लिए तैयार करते हैं।

रंजीत कपूर अपने चेखव के जरिए उनकी कहानी का भारतीय रूपांतरण नहीं करते। वे मात्र भाषिक रूपांतरण पर यकीन करते हैं, ताकि संवाद दर्शकों को संप्रेषित हो सके और रंगदर्शकों को हर समय यह महसूस होता रहे कि वे किसी रुसी कहानी का नाट्य रूपांतरण देख रहे हैं। ऐसा करते हुए वे अपने पात्रों की वेशभूषा, संगीत और मंच सभी कुछ रुसी रखते हैं और ऐसा करते हुए वे बेहद सफल हुए। मिर्जा मसूद भी इसी ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन निर्देशन की कमजोरियां स्वतः उजागर है। 'एक कलाकृति' के मंचन में डॉक्टर की दवाओं पर लगा लेबल रुसी भाषा में थे, जो ट्रीटमेंट के अनुरूप उचित ही था, तो 'बदला' की रंग प्रस्तुति में एक दुकान 'इरन एंड कंपनी' का लेबल भी रुसी में ही रहना था।

रंजीत कपूर के चेखव का अभिनय पक्ष बहुत ही सशक्त था। मिर्जा मसूद के चेखव का अभिनय पक्ष कुल मिलाकर बहुत साधारण था- कुछ रंगकर्मियों के सशक्त अभिनय के बावजूद। डॉक्टर व इवान की भूमिका में बिजोय महापात्र, वकील व दुकानदार के रूप में ज्वाला कश्यप, नताशा व आइरीन के रूप में किरण शर्मा, चुबूकोब (घनश्याम सेन्द्रे), लोमोव (कैलाश शादाब), तथा नतालिया की भूमिका में चित्रलेखा गिरेपुंजे ने अच्छा अभिनय किया। 19-20 लोगों की टीम के अभिनय की छाप इन्हीं 5-6 लोगों के बल पर बनती है।

रंजीत कपूर ने 'चेखव' की तरह ही मिर्जा मसूद के 'चेखव' में भी चीख-चिल्लाहट की जगह संवाद संप्रेषणीयता को प्राथमिकता दी गई है। यह संप्रेषणीयता इतनी सशक्त हैं कि दर्शक क्षेत्र में से रहा बच्चा भी नाटक से ध्यान नहीं भटका पाता।

पिछली बार की प्रस्तुति की तरह मुक्ताकाश पर फिर एक बार अच्छी प्रस्तुति देखने को मिली। इस अच्छी प्रस्तुति में रंजीत कपूर के 'चेखव' की प्रेरणा कितनी थी, यह तो मिर्जा मसूद ही बता सकते हैं।

संजय पराते

(लेखक की टिप्पणी-
बतौर एक दर्शक ही)

- खेल - गांव की मिट्टी से राजधानी तक...
- व्यंग्य- ये अंदर की बात है...
- महिला दिवस :- हक के लिए जागरूकता
- **लघुकथा** : पीछे छूटता हुआ गांव
- गुड़ी के गोठ : आदि परब के अद्भुत रंग
- आंखन देखी दुनिया : अज्ञान रोकना विकास की राह

और बहुत कुछ ...विविध, साहित्य, खेल, फिल्म, बहुत सी पहेलियां भी

हॉकर या बुक स्टॉल से हासिल करें या इन नंबरों पर पता नोट कराएं

राजमन तिवारी 98936-25006
डी.के. शर्मा 98271-64315